चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

बिजली चली गयी
1800–345–1111

रजि.न.34300/80 | संख्या 241 | श्री विजय पुरम, बुधवार , 09 सितम्बर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

अण्डमान द्वीपसमूह की तेजी से बढ़ती बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीएआरसी के वैज्ञानिक स्मॉल मोड्यूलर रिएक्टर्स के संभावित स्थानों का मूल्यांकन कर रहे

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्मॉल मोड्यूलर रिएक्टर्स की स्थापना के लिए संभावित स्थलों का आकलन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) के वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया है। यह कदम मलाका जलडमरूमध्य के पास भारत द्वारा रणनीतिक और नागरिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच द्वीपसमूह की ऊर्जा क्षमता को मजबूत कर सकता है।

परमाणु ऊर्जा विभाग की एक टीम 4 से 8 सितंबर तक द्वीपों के दौरे पर है और तीनों ज़िलों में संभावित स्थलों का आकलन कर रही है। यह अभ्यास द्वीपसमूह की तेजी से बढ़ती बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्मॉल मोड्यूलर रिएक्टर्स की संभावनाओं का पता लगाने की सिफारिश के बाद किया जा रहा है। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के आकार लेने के साथ बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट और डीप–वाटर मल्टीपरपोज पोर्ट्स शामिल हैं।

बीएआरसी की टीम ने एडमिरल डी.के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी को संभावित स्थलों तथा प्रस्तावित स्मॉल मोड्यूलर रिएक्टर्स योजना की अन्य विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी।

प्रस्तावित एसएमआर साइट्स का महत्व ग्रेट निकोबार प्रोजक्ट की पृष्ठभूमि में और बढ़ जाता है, जो इस क्षेत्र में भारत की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा पहलों में से एक है। इस परियोजना में गलाथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट, एक टाउनशिप और संबंधित पॉवर इन्फ्रेस्ट्रक्चर की परिकल्पना की गई है। सरकार ने इस परियोजना को रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है।

इस परियोजना का उद्देश्य अण्डमान सागर और दक्षिण–पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के साथ–साथ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के निकट एक प्रमुख मैरिटाइम हब स्थापित करना भी है।

इसका स्थान इसे व्यापार और कनेक्टिविटी से आगे भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह ऐसे समय में सामने आया है जब भारत पूर्वी हिंद महासागर में अपने आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव का विस्तार करने तथा क्षेत्र में मैरिटाइम एक्टिविटी की निगरानी करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट रूप से ग्रेट निकोबार प्रोजक्ट को रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। सरकार ने कहा है कि द्वीप पर एक मजबूत और स्थायी रक्षा उपस्थिति भारत को मैरिटाइम रूट्स की निगरानी और सुरक्षा में मदद करेगी।

इस रणनीति में स्ट्रेट ऑफ मलाका का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्रमुख मैरिटाइम चोकप्वाइंट है और हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के बीच वैश्विक व्यापार एवं एनर्जी सप्लाइज की बड़ी मात्रा इसी मार्ग से गुजरती है। ग्रेट निकोबार का स्थान भारत को जलडमरूमध्य के पश्चिमी एप्रोचस के निकट एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। (स्रोत: https://timesofindia.indiatimes.com/)

संदेश

'9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026' के अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समस्त

द्वीपवासियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

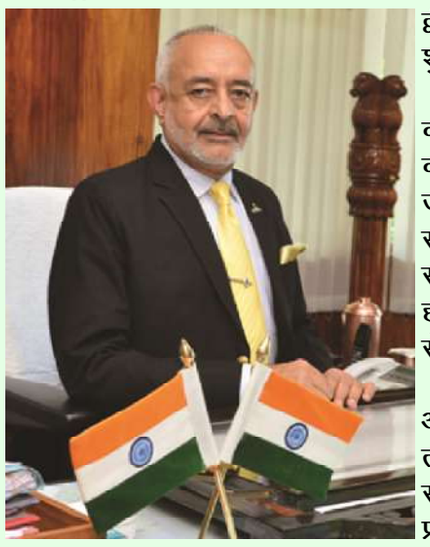

पोषण एक स्वस्थ, सक्षम एवं समृद्ध समाज की आधारशिला है। इस वर्ष के पोषण माह का विषय "हमारी आंगनवाड़ी, हमारी ज़िम्मेदारी", जो आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, देखभाल, सीखने एवं बाल्यावस्था के समग्र विकास के सशक्त केंद्रों के रूप में सुदृढ़ करने की हमारी सामूहिक उत्तरदायित्व को सार्थक रूप से रेखांकित करती है।

माह–भर चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत आहार में विविधता, पर्याप्त प्रोटीन का सेवन, ताजा एवं गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक सहभागिता एवं उत्तरदायित्व, बाल्यावस्था के प्रारंभिक विकास तथा 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जा रहा है।

'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी' एवं 'पोषण 2.0' के माध्यम से आहार में विविधता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बाल्यावस्था के प्रारंभिक विकास तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्थानीय निकायों एवं सामुदायिक भागीदारों के सहयोग से द्वीप प्रशासन, इन प्रयासों का लाभ द्वीपों के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं सभी अभिभावकों, देखभालकर्ताओं, युवाओं एवं समुदाय के सदस्यों से आह्वान करता हूँ कि वे पोषण माह में सक्रिय रूप से सहभागी बनें तथा पोषण को एक साझा दायित्व एवं सामूहिक संकल्प के रूप में अपनाएँ।

आइए, हम प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को देखभाल, पोषण एवं सीखने का सशक्त केंद्र बनाएं और सामूहिक प्रयासों से द्वीपसमूह को स्वस्थ एवं सुपोषित बनाते हुए एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें।

डी.के. जोशी

(एडमिरल डी. के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
एवं
उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी

आरोग्यसेतु 2.0 के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 29 जून, 2026 को शुरू किया गया आरोग्यसेतु 2.0, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत उपलब्ध एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) अनुप्रयोग है। यह विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को एक साथ उपलब्ध कराता है, जिससे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाएं अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनती हैं।

आरोग्यसेतु 2.0 एक डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग है, जो नागरिकों को अपना आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) बनाने और उसका प्रबंधन करने तथा अपने डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने में सहायता करता है। यह सहमति–आधारित स्वास्थ्य सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता यह नियंत्रित कर सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य अभिलेखों तक कौन पहुंच सकता है। यह ऐप कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ओसीआर तकनीक का उपयोग करके कागज़ पर उपलब्ध चिकित्सा दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर उन्हें व्यवस्थित डिजिटल अभिलेखों में बदलता है। इसके अन्य प्रमुख सुविधाओं में स्मार्ट रिपोर्ट, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के लिए स्कैन एवं पंजीकरण, स्कैन एवं भुगतान, अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेली–परामर्श, स्वास्थ्य एवं कल्याण की निगरानी, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की खोज, पीएम–जेएवाई संबंधी जानकारी, पारिवारिक स्वास्थ्य प्रबंधन, रक्त की उपलब्धता और एआई आधारित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शामिल हैं। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत नागरिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाएं अधिक सुलभ, व्यवस्थित तथा डिजिटल रूप से एक–दूसरे से जुड़ी हुई बनती हैं।

एबीडीएम के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा)/स्वास्थ्य आईडी नागरिकों को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान प्रदान करता है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेखों तक सुरक्षित पहुंच संभव होती है और रोगी की सहमति के आधार पर उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थानों

शेष पृष्ठ 4 पर

15 माह के बच्चे की फेफड़े की मेजर मिनिमली इनवेसिव लंग सर्जरी सफलतापूर्वक की गई

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

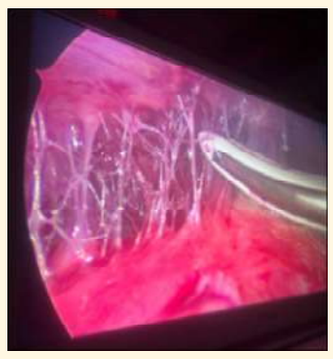

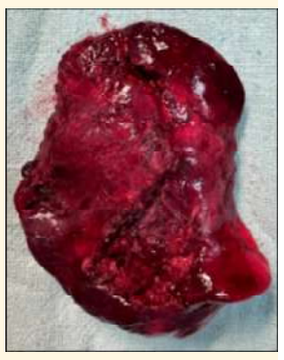

द्वीपसमूह में बाल शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, 1 वर्ष 3 माह की बच्ची के फेफड़े की एक मेजर मिनिमली इनवेसिव लंग सर्जरी जीबी पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम में सफलतापूर्वक की गई।

बच्ची को आठ माह की उम्र से बार–बार फेफड़ों के संक्रमण और निमोनिया की शिकायत थी। एक बार उसे लगभग छह सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था, जहां बाल रोग विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में उसे अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाएं दी गई थीं। हाल की बीमारी के दौरान बाल शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया। छाती की सीटी स्कैन जांच में कंजेनिटल सिस्टिक एयरवे मैलफॉर्मेशन (सीसीएएम/सीपीएएम) नामक फेफड़े की एक दुर्लभ जन्मजात असामान्यता का पता चला।

बच्ची की थोरेकोस्कोपिक–सहायता प्राप्त दाहिनी ऊपरी लोबेक्टॉमी की गई। इतनी कम उम्र के बच्चे में यह एक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें मिनिमली इनवेसिव तकनीकों के माध्यम से फेफड़े के प्रभावित हिस्से को निकाल दिया गया। तीन घंटे चली इस सर्जरी को मिनिमल एक्सेस एवं बाल शल्य चिकित्सक प्रोफेसर डॉ. सजी वर्गीस और बाल शल्य चिकित्सक डॉ. अनीस अख़्तरख़ावरी ने

शेष पृष्ठ 4 पर

'अनिम्स' ने वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

वैज्ञानिक उत्कृष्टता, ज्ञान के आदान–प्रदान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता की भावना अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा संस्थान (अनिम्स) में केंद्र में रही। 'अनिम्स' ने जीपीएचएआर के सहयोग से "विज्ञान को आगे बढ़ाना। परिवारों को सशक्त बनाना।" विषय के तहत 6–7 सितंबर, 2026 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा समकालीन स्वास्थ्य चुनौतियों और चिकित्सा, सार्वजनिक

शेष पृष्ठ 4 पर

लॉ कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यशाला संचालित

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

कठिन शैक्षणिक वातावरण में शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य की व्यापक समझ आवश्यक है, यह बात टेली–मानस परामर्शदाता श्रीमती माधवी नांबियार ने कही। विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह (दिवस 10 सितंबर को है) के आयोजन के तहत अण्डमान लॉ कॉलेज (एएलसी) में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंगलवार को अण्डमान लॉ कॉलेज में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक दृढ़ता विकसित करना, भावनात्मक कमज़ोरियों से जुड़े कलंक को दूर करना तथा विद्यार्थियों को स्वयं और अपने साथियों में गंभीर मानसिक तनाव के शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने में सक्षम बनाना था। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता के तहत कुछ गतिविधियां भी आयोजित कीं। 'साइन फॉर लाइफ' हस्ताक्षर एवं संकल्प ऐसी ही एक गतिविधि थी, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने एक साझा कैनवास पर आशा और आपसी एकजुटता का संदेश लिखा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं राज्यों के बीच नेटवर्किंग (टेली–मानस) की सेवा 24 घंटे

शेष पृष्ठ 4 पर

CMYK

स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेस्डर ने किया का एएनएसआई दौरा

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित एवं अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेस्डर श्री नरेश चंद्र लाल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत की जा रही तैयारियों के सिलसिले में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के अण्डमान तथा निकोबार क्षेत्रीय केंद्र, श्री विजय पुरम का दौरा किया।

यह दौरा वर्ष 2026 के स्वच्छ भारत विषय "स्वच्छ भारत, मेरी ज़िम्मेदारी" की भावना के अनुरूप आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्यकर आदतों तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के प्रति व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया गया।

दौरे के दौरान श्री नरेश चंद्र लाल ने क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिक कर्मचारियों एवं अन्य कार्मिकों से बातचीत की और संस्थागत परिसरों तथा सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता एवं साफ–सफाई बनाए रखने में सामूहिक ज़िम्मेदारी के महत्व पर ज़ोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन एवं विशेष अभियान 6.0 के उद्देश्यों के अनुरूप, प्रतिभागियों को स्वच्छ एवं स्वच्छतापूर्ण वातावरण बनाए रखने में स्वच्छता कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान तथा उनकी गरिमा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए "सफाई मित्र" पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

श्री लाल ने "स्वच्छता ही सेवा" के महत्व पर प्रकाश डाला और क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिक कर्मचारियों एवं कार्मिकों को स्वच्छता एवं जागरूकता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि दौरे का समापन श्रमदान तथा स्वच्छता के प्रति व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देने के साथ हुआ, जिससे "स्वच्छ भारत, मेरी ज़िम्मेदारी" के संदेश को और मजबूत किया गया। भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र ने स्वच्छ भारत मिशन, विशेष अभियान 6.0, स्वच्छता ही सेवा तथा स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों में तैयारियों के चरण के दौरान और इसके बाद भी सक्रिय रूप से भाग लेने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

मायाबंदर में आत्महत्या रोकथाम को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर आज महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय (एमजीसीसी), मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला के सम्मेलन कक्ष में आत्महत्या रोकथाम पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्महत्या रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण तथा समय पर सहायता प्राप्त करने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सत्र में डॉ. आथिरा जे. प्रकाश, मनोचिकित्सक सहित संसाधन व्यक्तियों की टीम ने भाग लिया। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की और आत्म–जागरूकता को बढ़ावा देने तथा भावनात्मक कल्याण पर खुलकर चर्चा करने के लिए कुछ रोचक गतिविधियां आयोजित कीं।

सुश्री प्रेरणा, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक और श्री सुरजीत रॉय, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक चुनौतियों, मानसिक परेशानी के शुरुआती संकेतों की पहचान तथा पेशेवर सहायता एवं सहयोग के लिए समय पर संपर्क करने के महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

आतंकवादी पीड़ितों के पति/पत्नी और बच्चों के लिए केंद्रीय पूल से 4 एमबीबीएस सीटें निर्धारित

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सीटीसीआर प्रभाग के अवर सचिव से प्राप्त पत्र के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2026–27 में नामांकन के लिए निम्नलिखित चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में आतंकवादी पीड़ितों के पति/पत्नी एवं बच्चों के लिए केंद्रीय पूल से 4 (चार) एमबीबीएस सीटें निर्धारित की गई हैं:–

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	शहर	राज्य	सीटों की संख्या
1.	ए.एन. मगध मेडिकल कॉलेज	गया	बिहार	01 (एक)
2.	ग्रांट मेडिकल कॉलेज	मुंबई	महाराष्ट्र	01 (एक)
3.	पं. जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज	रायपुर	छत्तीसगढ़	02 (दो)
	कुल			04 (चार)

मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि आतंकवाद से प्रभावित नागरिक पीड़ितों के पति/पत्नी अथवा बच्चों को उपर्युक्त एमबीबीएस सीटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है:–

(क) प्राथमिकता–1: ऐसे बच्चे, जिनके दोनों माता–पिता आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं।

(ख) प्राथमिकता–2: ऐसे परिवारों के बच्चे, जिनके एकमात्र कमाने वाले सदस्य की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई है।

(ग) प्राथमिकता–3: आतंकवादी गतिविधियों के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग एवं गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के आश्रित।

पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:–

(1) उम्मीदवार आतंकवाद के मृतक/दिव्यांग नागरिक पीड़ित का पति/पत्नी अथवा बच्चा होना चाहिए।

(2) प्रवेश के समय उम्मीदवार की आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो अथवा स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के वर्ष की 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता हो तथा वह भारतीय नागरिक हो।

(3) शैक्षणिक योग्यता : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमों के अनुसार, उम्मीदवार को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेज़ी विषयों में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी को एक साथ लेते हुए अनारक्षित एवं सामान्य–ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए अनारक्षित एवं सामान्य–ईडब्ल्यूएस वर्ग में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(4) एनईईटी (यूजी)–2026 में अर्हता प्रतिशतक: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमों के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए अनारक्षित एवं सामान्य–ईडब्ल्यूएस वर्ग में न्यूनतम 50वां प्रतिशतक तथा एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग में 40वां प्रतिशतक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए अनारक्षित एवं सामान्य–ईडब्ल्यूएस वर्ग में न्यूनतम 45वां प्रतिशतक तथा एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग में 40वां प्रतिशतक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रतिशतक का निर्धारण एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा।

तदनुसार, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–1) में आवेदन, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ दो प्रतियों में, उन इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाते हैं, जो आतंकवाद से प्रभावित नागरिक पीड़ितों के पति/पत्नी एवं बच्चों के लिए केंद्रीय पूल से निर्धारित उक्त एमबीबीएस सीटों के आवंटन के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ों, जिसमें आतंकवाद से प्रभावित नागरिक पीड़ित होने का दस्तावेज़ी प्रमाण भी शामिल है, के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन विकास–4 अनुभाग, सचिवालय, श्री विजय पुरम में व्यक्तिगत रूप से 11 सितंबर, 2026 को शाम 3 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा किया जा सकता है। अपूर्ण आवेदन को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त निर्धारित तिथि एवं समय की समाप्ति के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

समावेशी शिक्षा के तहत सीडब्ल्यूएसएन के लिए भाषा क्लब का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

समावेशी शिक्षा पहल के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए भाषा क्लब का शुभारंभ राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सुभाषग्राम, डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान स्थित भाषा प्रयोगशाला में किया गया। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2026 के अवसर पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत खंड परियोजना कार्यालय, डिगलीपुर द्वारा इस पहल का आयोजन डॉ. (श्रीमती) सी. पुष्पवल्ली, खंड परियोजना अधिकारी, बीपीओ, डिगलीपुर की उपस्थिति में किया गया। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भाषा विकास को बढ़ावा देना तथा साक्षरता संबंधी गतिविधियों में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

60वां अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 'लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता' विषय के तहत मनाया गया। इस अवसर पर साक्षरता को प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक मानव अधिकार के रूप में रेखांकित किया गया तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) सहित प्रत्येक बच्चे को साक्षरता कौशल विकसित करने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि इलंचेलियन, उप–प्रधान, ग्राम पंचायत सुभाषग्राम द्वारा किया गया। यह समावेशी साक्षरता संबंधी पहलों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लॉ कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता ——————पृष्ठ 1 का शेष

उपलब्ध है। इसका टोल–फ्री नंबर 14416 है और यह पूरे भारत में निःशुल्क, गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से इसे आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया।

प्राचार्य डॉ. पी.वी.एन. सरमा ने अपने संबोधन में विधि के विद्यार्थियों और कानूनी पेशेवरों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। सत्र में डॉ. राजीव मंडल, मानसिक स्वास्थ्य समन्वयक उपस्थित रहे। संकाय सदस्य सुश्री निशा सिकदार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

'अनिम्स' ने वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और बेहतर ——————पृष्ठ 1 का शेष

स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा नवाचार के क्षेत्र में उभरते विकास पर विचार–विमर्श किया।

वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन 6 सितंबर, 2026 को 'अनिम्स' के निदेशक डॉ. मुकेश त्रिपाठी एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. सिद्धराजु ने किया।

समारोह की शुरुआत 5 सितंबर, 2026 को 'अनिम्स' में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के साथ हुई, जिसमें चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. लोकेन्द्र शर्मा, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, टोंक, डॉ. प्रमोद शंखपाल, अपर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी, टीएन मेडिकल कॉलेज, मुंबई तथा डॉ. अशोक पाल गोबिंद, एसोसिएट प्रोफेसर, एनाटॉमी, 'अनिम्स' के मार्गदर्शन में किया गया।

शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया, जहां समकालीन स्वास्थ्य सेवा संबंधी चुनौतियों पर वैज्ञानिक विचार–विमर्श और ज्ञान का आदान–प्रदान किया गया। रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), निवारक औषध विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सहित प्रमुख विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान, संवादात्मक सत्रों, कार्यशालाओं तथा शोध–पत्र और पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से चर्चा की जा रही है।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह साझा संदेश दिया गया कि ज्ञान, संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक नवाचार, समर्पित नेतृत्व और सामूहिक प्रयास एक स्वस्थ, सशक्त और अधिक सक्षम समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

15 माह के बच्चे की फेफड़े की मेजर ——————पृष्ठ 1 का शेष

अपनी शल्य चिकित्सा टीम के साथ मिलकर किया।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस प्रक्रिया में डॉ. नारायण, एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष, डॉ. रम्या नायडू, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तथा उनकी टीम का सहयोग रहा। सर्जरी के बाद बच्ची की सर्जिकल आईसीयू में बाल रोग एवं बाल गहन चिकित्सा टीमों के सहयोग से करीबी निगरानी की गई।

बच्ची की स्थिति में उत्कृष्ट सुधार हुआ और उसे सर्जरी के सातवें दिन स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

सीसीएएम/सीपीएएम एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी है, जो बच्चों में बार–बार संक्रमण और निमोनिया का कारण बन सकती है तथा प्रभावित फेफड़े के हिस्से या लोब को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालने की आवश्यकता हो सकती है।

इस जटिल मामले का सफल उपचार जीबी पंत अस्पताल में विशेषज्ञ बाल शल्य चिकित्सा एवं मिनिमली इनवेसिव शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता तथा उन्नत शल्य चिकित्सा, एनेस्थीसिया और गहन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को दर्शाता है। यह भी साबित करता है कि जटिल बाल शल्य चिकित्सा संबंधी बीमारियों का उपचार द्वीपसमूह में ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जिससे परिवारों को उपचार के लिए मुख्यभूमि भारत की यात्रा करने की आवश्यकता कम हो रही है।

इस सफल परिणाम को बाल शल्य चिकित्सा, मेजर मिनिमली इनवेसिव शल्य चिकित्सा, एनेस्थीसिया, सर्जिकल आईसीयू, बाल रोग तथा बाल गहन चिकित्सा टीमों के बीच बेहतर टीमवर्क और समन्वय के माध्यम से संभव बनाया गया।

आरोग्यसेतु 2.0 के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल ——————पृष्ठ 1 का शेष

के बीच निर्बाध रूप से साझा किया जा सकता है।

आरोग्यसेतु 2.0 पीएचआर अनुप्रयोग के माध्यम से उपलब्ध स्कैन एवं शेयर सुविधा नागरिकों को सहभागी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करने और रोगी की सहमति से अपने आभा संबंधी विवरण साझा करने में सक्षम बनाती है, जिससे ओपीडी पंजीकरण शीघ्र किया जा सकता है। यह डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया प्रतीक्षा समय को कम करने, मरीज़ों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में कतार प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता करती है। नागरिकों को आरोग्यसेतु 2.0 अनुप्रयोग के माध्यम से स्कैन एवं शेयर सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि ओपीडी पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक तेज, सुविधाजनक और प्रभावी हो सके।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार नागरिकों को आरोग्यसेतु 2.0 डाउनलोड करके उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे अपना आभा बना और उसका प्रबंधन कर सकें, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त कर सकें तथा विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। इससे अधिक सुलभ, प्रभावी और मरीज़–केंद्रित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के निर्माण में योगदान मिलेगा।

यूटी खेल नीति–2026 का मसौदा तैयार, 15 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

खेल एवं युवा कार्य विभाग ने राष्ट्रीय खेल नीति 'खेलो भारत नीति–2025' के अनुरूप यूटी खेल नीति–2026 का मसौदा तैयार किया है। इसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट **https://andamannicobar.gov.in/** तथा खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट **https://sports.andamannicobar.gov.in/** से डाउनलोड किया जा सकता है। नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी हितधारकों एवं आम जनता से अण्डमान तथा निकोबार संघ राज्य क्षेत्र खेल नीति–2026 के मसौदे पर अपने विचार एवं सुझाव 15 सितंबर, 2026 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। टिप्पणियां एवं सुझाव निदेशालय खेल एवं युवा कार्य, नेताजी स्टेडियम के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। सुझाव ई–मेल के माध्यम से **directorsportsani@gmail.com** पर भी भेजे जा सकते हैं।

आज़ाद नगर में लगा पशुओं के स्वास्थ्य एवं बांझपन जांच शिविर

श्री विजय पुरम, 8 सितंबर।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने पशुओं के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार तथा समय पर जांच और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से डेयरी किसानों को सहायता प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत आज मॉडर्न विलेज, आज़ाद नगर, बम्बूफ्लाट, दक्षिण अण्डमान में स्वास्थ्य–सह–बांझपन जांच शिविर का आयोजन किया।

शिविर के दौरान कुल 33 गायों की जांच की गई। इनमें अंडाणुहीनता (एनोएस्ट्रस) के दो मामले पाए गए, जबकि बांझपन का कोई मामला सामने नहीं आया। चिन्हित मामलों के प्रबंधन के लिए पशुपालकों को आवश्यक सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान किसानों को पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं उत्पादकता के लिए वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को आहार देने एवं उनके प्रबंधन, समय पर कृमिनाशक दवा देने तथा टीकाकरण के संबंध में सलाह दी गई। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन एआई भी शामिल है, जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। इन सेवाओं से गर्भधारण की दर में सुधार करने तथा डेयरी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 04 सितम्बर, 2026

सं. 255/2026 फा. सं. 2–116/2026–राजस्व, जनगणना नियमावली, 1990 के नियम–8 (iaa) के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 14.08.2026 के पत्र सं. 9/10/2025-CD (Cen.) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 14 अगस्त, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4505 (अ). को एतद्द्वारा आम जनता की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

ह./–
सहायक सचिव (राजस्व)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4505 (अ).– केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (37 का 1948) की धारा 8 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुदेश और निर्देश देती है कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए, जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिनके लिए उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया है, उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में सभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, अर्थात :

1. व्यक्ति का नाम
2. मुखिया से संबंध
3. लिंग
4. जन्म तिथि और आयु (पूर्ण वर्षों में)
5. वर्तमान वैवाहिक स्थिति
6. विवाह के समय आयु (पूर्ण वर्षों में)
7. पति/पत्नी का नाम
8. घोषित राष्ट्रीयता
9. धर्म
10. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/जाति
11. पिता का विवरण
12. माता का विवरण
13. निःशक्तता
14. मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान
15. साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति
16. शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति
17. प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय/विषय
18. पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया
19. आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी
20. व्यवसाय
21. उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप
22. कर्मी का वर्ग
23. गैर–आर्थिक कार्यकलाप (अल्पकालिक, अर्द्ध–अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)
24. काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध (अल्पकालिक, अर्द्ध–अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)
25. कार्यस्थल तक की यात्रा
26. जन्म स्थान
27. पूर्व निवास स्थान
28. स्थान परिवर्तन का कारण
29. स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गाँव/नगर में निवास की अवधि
30. स्थायी निवास स्थान का पता
31. वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
32. कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
33. पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए)
34. कोविड़–19 टीकाकरण का स्थान
35. बैंक खातों की कुल संख्या
36. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)
37. आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)
38. वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो)
39. पासपोर्ट नंबर (यदि भारतीय पासपोर्ट धारक हैं)
40. ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता

{फ़ा. सं. 9/8/2025–सीडी (सीइएन)}

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

परियोजना निदेशक का कार्यालय
अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी (अ.नि.ए.नि.सो.)

सूचना

F.No. 1-4/ANACS/Facility level/2023/641 dt. 08.09.2026

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.08.2026 को आयोजित साक्षात्कार में परामर्शदाता (Counsellor), एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र (ICTC), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC), ननकौरी के पद पर भर्ती हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अंतिम रूप से तैयार कर ली गई है।

उक्त मेरिट सूची अण्डमान एवं निकोबार एड्स नियंत्रण सोसायटी (ANACS) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी मेरिट सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु सोसायटी की आधिकारिक वेबसाइट https://anacs.andamannicobar.gov.in मे देख सकते हैं।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

प्रशासनिक अधिकारी
अण्डमान तथा निकोबार एड्स कंट्रोल सोसायटी

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, सिप्पीघाट की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर (एन पी)/2025–26/191

कार्य का नाम : सीपीघाट, ग्राम पंचायत के अंर्तगत पंचायत द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़को की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव।

1) बिम्बलिटन 01 (जोडाकिलन) में गोसल मास्टर घर के पास से श्री हरि हरि राधे कृष्णा मंदिर तक ग्रामीण सड़क की मरम्मत और रखरखाव।

2) टेलराबाद वार्ड संख्या 04 लोअर तेलुगु बस्ती, में मोहम्मद अली के घर से तारकेश के घर तक ग्रामीण सड़क की मरम्मत और रखरखाव (पाँचवा कॉल)।

अनुमानित लागत : रु. 14,40,039/–, धरोहर राशि : रु. 28,801/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/09/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2025_RDPRI_21796_5

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

खबरों और रोचक जानकारियों के लिए पढ़िए
'द्वीप समाचार'

भारत–चीन संबंध धीरे–धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 08 सितंबर (हि.स.)। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत–चीन संबंध धीरे–धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने संबंधों को सामान्य बनाने में लोगों के बीच संपर्क को महत्वपूर्ण बताते हुए वीजा सुविधा को इसका प्रमुख हिस्सा बताया। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर निरंतर शांति और स्थिरता आवश्यक है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 6 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के वाचा और 7 सितंबर को चीन के दमाई में भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर पर पहली फ्लैग मीटिंग हुई।

प्रवक्ता ने कहा, "अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में क्रमशः बीजिंग और नई दिल्ली में हुई 'वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन' (डब्ल्युएमसीसी) की बैठकों में हुई चर्चाओं के आधार पर, वरिष्ठ सैन्य कमांडर–स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के वाचा और 7 सितंबर को चीनी तरफ़ दमाई में आयोजित की गई। पश्चिमी सेक्टर में भी इसी तरह की व्यवस्था मौजूद है।"

उल्लेखनीय है कि भारत–चीन संबंधों में साल 2025 से धीरे–धीरे सुधार के संकेत मिले हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई, सीधी उड़ानों और चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा की सुविधा बहाल हुई तथा नाथू ला जैसे सीमा व्यापार मार्गों को दोबारा खोला गया।

'पिकलबॉल वर्ल्ड कप' में 41 मेडल के साथ भारत ने हासिल किया चौथा स्थान

नई दिल्ली, 08 सितम्बर। भारत ने 'पिकलबॉल वर्ल्ड कप' में अपना सफर चौथे स्थान पर खत्म किया। वियतनाम के दा नांग में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कुल 41 मेडल (7 गोल्ड, 17 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल) जीते। भारतीय टीम पिछले साल 7वें स्थान पर रही थी। 48 खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए किड्स, जूनियर्स, ओपन, सीनियर्स और मास्टर्स टीम इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसके अलावा, 130 से ज्यादा खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत कैटेगरी में भी मुकाबला किया।

किड्स टीम का सिल्वर मेडल जीतना वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इस टीम की कमान वीर शाह के हाथों में थी। इसमें विरांष चोपड़ा, आरिन बल्लानी, महिका राठौड़, मानसी कार्तिक, आश्रिता एस, कवीर मेहता और प्रार्थना मोटियानी शामिल थे। भारतीय कप्तान को किड्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर भी सम्मानित किया गया।

भारतीय जूनियर टीम क्वार्टर–फाइनल में मजबूत वियतनाम टीम से हारकर चौथे स्थान पर रही। अर्जुन सिंह ने भारतीय जूनियर टीम की कप्तानी की, जिसमें आदित्य सिंह, देव शाह, पूर्वांश पटेल, विवान पटेल, नाओमी अमलसादीवाला, आश्रिता राजू और दिया मट्टीपति भी शामिल थे।

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत साइबर धोखाधड़ी पर कार्रवाई

नई दिल्ली, 08 सितम्बर। दूरसंचार विभाग ने अपने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत 22 मई 2025 को शुभारंभ किए गए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक –एफआरआई के माध्यम से 15 महीनों के भीतर संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी के 5000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान को सफलतापूर्वक रोका है। एफआरआई एक बहुआयामी विश्लेषणात्मक ढांचा है, इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए कार्रवाई योग्य, वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना है।

संचार मंत्रालय ने कहा है कि यह उपलब्धि उस पहल के निर्णायक विस्तार को दर्शाती है जिसने संचालन के पहले छह महीनों में 660 करोड़ रुपये के नुकसान को रोका था।

DISTRICT CHILD PROTECTION UNIT
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, NORTH & MIDDLE ANDAMAN DISTRICT, MAYABUNDER

INTERVIEW NOTICE

Dated the 07th September, 2026

A Personal Interview along-with Document Verification and Trade Test for the post of Accountant in DCPU, N&M Andaman is scheduled to be held on 16.09.2026 at 11.30 AM at Deputy Commissioner's Office, N&M Andaman district, Mayabunder.

All the eligible candidates are directed to present at 8.30 AM for Document Verification, Trade Test and Personal Interview at the District Child Protection Unit, Deputy Commissioner's Office, N&M Andaman district, Mayabunder. In view of this, an Eligible/In-eligible list of applications for the said post is uploaded on the Administration website i.e. (www.andaman.gov.in) and (https://northmiddle.andaman.nic.in/).

Any clarification regarding the above-mentioned recruitment can be obtained over telephone No. 03192-273127.

Assistant Commissioner (HQ),
North & Middle Andaman, Mayabunder

केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के लिए नियम के मुताबिक ही शुल्क लेने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 08 सितम्बर। केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां उपलब्ध कराते समय फोटो कॉपी का शुल्क केवल आरटीआई नियम, 2012 में निर्धारित दर के अनुसार लिया जाए।

आयोग ने सिफारिश की है कि सीबीएसई 19 मई, 2025 के अपने परिपत्र में संशोधन करे। आयोग ने पाया कि आरटीआई अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों को पुनर्मूल्यांकन की मांग करने से रोकने वाला प्रविधान पारदर्शिता संबंधी कानून की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। यह मामला सीबीएसई की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के एक परीक्षार्थी द्वारा दायर आरटीआई आवेदन से सामने आया।

परीक्षार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपियां मांगी थीं और उसने नियमित पुनर्मूल्यांकन(री–इवेल्युएशन) प्रक्रिया की अधिक लागत का हवाला दिया था। आवेदन में कहा गया था कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में पांच विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी के लिए 2,500 रुपये, अंकों के पुनः सत्यापन के लिए 2,500 रुपये और प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाता था, इससे कुल खर्च 10,000 रुपये तक पहुंच सकता था।

बोर्ड के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने दो जुलाई, 2025 को परीक्षार्थी को सूचित किया कि आवश्यक शुल्क प्राप्त होने के बाद मांगी गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां उसे ईमेल के जरिये भेज दी गई थीं। इसके बाद परीक्षार्थी ने प्रथम अपील दायर की। इसमें उसने उत्तर पुस्तिकाओं में खाली पन्नों, गणित में मॉडरेशन नीति और अपनी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से जुड़े सवाल उठाए।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने कहा कि ये मुद्दे मूल आरटीआई में शामिल सवालों से अलग थे और इनके लिए स्पष्टीकरण तथा विश्लेषणात्मक जवाब की आवश्यकता थी। सीआईसी की सुनवाई के दौरान सीपीआईओ ने 19 मई, 2025 को जारी सीबीएसई के एक परिपत्र का भी हवाला दिया।

इसमें कहा गया था कि आरटीआई अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका की प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इस अधिनियम के तहत अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता। सीआईसी ने इस प्रतिबंध पर आपत्ति जताई। आयोग ने कहा कि केवल इस वजह से कि किसी परीक्षार्थी ने आरटीआई के जरिये अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त की है, उसे पुनर्मूल्यांकन की मांग करने से रोकना आरटीआई अधिनियम और नियमों की भावना के विपरीत है। आयोग ने सीपीआईओ को भविष्य में पूरी सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी और सिफारिश की कि सीबीएसई अपने 19 मई 2025 के परिपत्र में संशोधन करके उसे आरटीआई अधिनियम के अनुरूप बनाए। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

वेदांता दिल्ली हाफ मैराथनः दो बार के चैंपियन बिरहानु लेगेसे की नजर तीसरे खिताब पर

नई दिल्ली, 08 सितम्बर (हि.स.)। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टार एथलीटों की घोषणा कर दी गई है। विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रोड रेस का आयोजन 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा। पुरुष वर्ग में इथियोपिया के दो बार के चैंपियन बिरहानु लेगेसे और महिला वर्ग में केन्या की 2022 की विजेता इरिन चेप्ताई आकर्षण का केंद्र होंगी।

प्रोकैम इंटरनेशनल की ओर से मंगलवार को घोषित एलीट खिलाड़ियों की सूची में बिरहानु लेगेसे 58 मिनट 59 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ सबसे तेज धावक हैं। महिला वर्ग में इरिन चेप्ताई का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 64 मिनट 53 सेकंड है।

इस प्रतिष्ठित दौड़ में दुनिया के शीर्ष दूरी के धावक हिस्सा लेंगे। कुल पुरस्कार राशि 2,75,732 अमेरिकी डॉलर रखी गई है, जबकि पुरुष और महिला वर्ग के विजेताओं को 27,000–27,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। दोनों वर्गों में दसवें स्थान तक के धावकों को पुरस्कार राशि दी जाएगी। शीर्ष भारतीय धावकों के लिए अलग प्रोत्साहन राशि भी होगी। इसके अलावा अपने वर्ग का पिछला आयोजन रिकॉर्ड तोड़ने वाले एलीट धावक को 12,000 अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड बोनस दिया जाएगा।

पुरुष वर्ग में बिरहानु लेगेसे के अलावा सात ऐसे धावक शामिल हैं, जिनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 60 मिनट से कम है। इससे इस साल की पुरुष दौड़ के बेहद प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। केन्या के चार्ल्स माताता भी चुनौती पेश करेंगे, जो 2023 में दिल्ली हाफ मैराथन में उपविजेता रहे थे और इस साल इस्तांबुल हाफ मैराथन में भी दूसरे स्थान पर रहे।

इथियोपिया के डेरिबा टेस्फाये और मेलाकु बेलाचेव भी पुरुष वर्ग को मजबूती देंगे। डेरिबा रॉटरडैम मैराथन में दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मेलाकु ने 2026 हांगकांग मैराथन का खिताब जीता है।इस वर्ष की वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में दुनिया के शीर्ष 36 एथलीट हिस्सा लेंगे। इनमें 18 पुरुष और 18 महिला धावक शामिल हैं, जो पुरुष और महिला वर्ग के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दी

नई दिल्ली, 08 सितम्बर। भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर, ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। ब्रिटेन ने यह राहत अपनी कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था – सीबीएएम के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर, भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इनमें इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं।

इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। यह फैसला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही तकनीकी वार्ता के बाद हुआ है। हालांकि, राहत की मात्रा भारत में वास्तव में चुकाए गए कार्बन मूल्य और ब्रिटेन के नियमों के तहत जरूरी प्रमाण और सत्यापन पर निर्भर करेगी। ब्रिटेन वर्ष 2027 से सीबीएएम लागू करने वाला है, इसलिए भारत के कार्बन–गहन उत्पादों के निर्यात के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इतिहास के पन्नों में 09 सितम्बर : आज ही के दिन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना केंद्रीय विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 08 सितम्बर (हि.स.)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) देश के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इसके इतिहास की शुरुआत समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने और भारतीय मुसलमानों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से इस संस्थान की नींव रखी थी। समय के साथ यह शिक्षण संस्थान देश में उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ।

09 सितंबर 1920 को भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित कानून के तहत मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। इसी के साथ यह भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया। एएमयू ने शिक्षा, शोध, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, कानून और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश को बड़ी संख्या में विद्वान, वैज्ञानिक, प्रशासक और अन्य पेशेवर दिए हैं। विश्वविद्यालय का इतिहास भारतीय शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण अध्यायों से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष 09 सितंबर एएमयू के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है, जब 1920 में इस संस्थान ने विश्वविद्यालय के रूप में एक नई पहचान हासिल की थी।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1776 – अमेरिकी संसद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम 'यूनाइटेट कॉलोनीज़' से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया।

1867–यूरोपीयीय देश लक्जमबर्ग ने स्वतंत्रता हासिल की।

1915 – प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी सचिन्द्रनाथ सान्याल और अंग्रेज़ों के बीच उड़ीसा के काप्टेवाड़ा में संघर्ष।

1939 – नाजी सेना पौलेंड की राजधानी वारसा पहुंची।

1949 – भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।

1939–द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी सेना वर्साय पहुँची।

1948 – यूएसएसआर की मदद से किम II–संग ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाया।

1954–अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भूकंप से 1400 लोग मरे।

1965 – तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र बना।

1967 – युगांडा ब्रिटेन से आजाद हुआ।

1976 – चीन के मार्क्सवादी नेता माओ जेडोंग की मौत हुई थी। 1949 में कम्युनिस्ट टेकओवर के बाद की अवधि में उनका चीन पर प्रभुत्व रहा।

1979–जोगेन्द्रनाथ हजारिका ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया।

1991–तजाकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की।

1998 – अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की प्रकरण पर स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार ने अपनी बहुचर्चित रपट कांग्रेस को प्रेषित किया।

1999 – भारत के महेश भूपति तथा जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल ख़िताब जीता।

2001 – वीनस विलियम्स ने छोटी बहन सेरेना को ग्रैंडस्लैम फ़ाइनल में हराया।

2005 – चीन के बीजिंग स्थित छाओयांग पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण।

2006 – अंतरराष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर इजराइल द्वारा आठ सप्ताह से की गयी लेबनान की नौसैनिक घेराबन्दी को समाप्त किया गया।

2006–अमेरिकी राज्य फ़्लोरिडा के केप कनैवरल स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यान अटलांटिस ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी।

स्किलिंग का नया मंत्रः डिजिटल पासपोर्ट, स्किल एक्सचेंज और स्किल स्कोर पर काम करेगी सरकार

नई दिल्ली, 08 सितम्बर।

सरकार स्किलिंग के नए मंत्र पर काम करने जा रही है। इनमें मुख्य रूप में डिजिटल स्किलिंग पासपोर्ट, स्किलिंग एक्सचेंज और स्किलिंग स्कोर शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में इंटीग्रेटेड स्कीम इन स्किलिंग आर्किटेक्चर (आईएसएसए) आरंभ करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। इस स्कीम के तहत नीति आयोग की सिफारिश में सुझाए गए नए मंत्र पर अमल हो सकता है।

स्किलिंग के लिए इन तीन तरीकों को अपनाने से नौकरी देने वाले और खोजने वाले दोनों को आसानी होगी। अभी लोन लेने दौरान बैंक उस व्यक्ति के पुराने रिकार्ड को जानने के लिए सिबिल स्कोर चेक करता है। वैसे ही किसी व्यक्ति के स्किल, योग्यता, काम की भूमिका की जानकारी डालकर व्यक्ति का फ्यूचर रेडिनेस इंडेक्स या स्किल स्कोर का पता किया जा सकेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से चलने वाला यह टूल बता देगा कि वह व्यक्ति भविष्य की टेक्नोलाजी व उद्योग जगत में होने वाले बदलाव में कितना उपयोगी रहेगा। डिजिटल स्किल पासपोर्ट में व्यक्ति अपने सभी स्किल को एक जगह बता सकेगा और भविष्य में जो भी स्किल वह हासिल करता है, वह सब उसके स्किल पासपोर्ट में जुड़ता जाएगा।

नीति आयोग का कहना है कि ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक एकाउंट रजिस्ट्री (अपार) पहचान नंबर की तरह डिजिटल पासपोर्ट भी तैयार किया जा सकता है। डाटा पर आधारित स्किलिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए आयोग ने राज्य स्तर पर डिजिटल स्किल एक्सचेंज बनाने की सिफारिश की है।

डिजिटल एक्सचेंज से निजी उद्योग जगत व सरकार की संस्था जुड़े होंगे। यहां स्किल्ड व्यक्ति अप्रेंटिसशिप और पार्ट टाइम नौकरी भी ढूंढ़ सकेंगे। कम या गैर स्किल्ड श्रमिकों को जरूरतमंद उद्यमियों से आसानी से मिलाने के लिए मोबाइल आधारित वर्कफोलियो प्लेटफार्म बनाने की सिफारिश की गई है।

स्किलिंग का प्रोग्राम पिछले 11 सालों से चल रहा है और इस अवधि में करीब 7.6 करोड़ लोगों को विभिन्न रूप में स्किल किया गया। नीति आयोग का मानना है कि जितने बड़े पैमाने पर लोग स्किल किए गए, उसका फायदा अर्थव्यवस्था को नहीं मिला। क्योंकि इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक स्किल नहीं किए गए।

अब वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक अरब से अधिक लोगों को स्किल करना होगा। इसलिए घरों में काम करने वाले, स्वास्थ्य की वजह से कोई काम नहीं करने वालों के साथ उन युवाओं को भी स्किल किया जाना चाहिए जो न तो पढ़ाई और न ही कोई काम कर रहे हैं। आयोग ने जर्मनी, साउथ कोरिया, आस्ट्रेलिया जैसे देशों के तर्ज पर स्कूल से ही स्किलिंग शुरू करने के लिए कहा है। स्कूल के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए कहा गया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धियों को मिली पहचान, डब्ल्यूएचओ ने किया सम्मानित

नई दिल्ली, 08 सितम्बर (हि.स.)।

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र में महत्वपूर्ण सम्मान मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने भारत की ओर से दो प्रतिष्ठित विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

पुरस्कार लेने के बाद खुशी जाहिर करते हुए श्री जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा कि भारत को पिछले एक दशक से मातृ एवं नवजात टिटनेस के उन्मूलन को बनाए रखने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से गैर–संचारी रोगों से प्रभावी ढंग से निपटने में नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाई है तथा संक्रामक और गैर–संचारी दोनों प्रकार की बीमारियों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत, अमेरिका और 24 देशों के साथ ग्लोबल 6जी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अलायंस में शामिल

वाशिंगटन, 08 सितंबर (हि.स.)।

संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने सोमवार को कहा कि भारत अगली पीढ़ी के 6 जी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के अलायंस में शामिल हो गया है। इसके अलावा अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने जी 20 इनोवेशन मिनिस्टीरियल के दौरान भारत के वाणिज्य राज्यमंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात कर 6जी के भविष्य पर चर्चा की।

अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने एक्स पर कहा,'' हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ उस कोशिश में शामिल हो गया है जिसका मकसद यह पक्का करना है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क हमारी साझा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करें। हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और 6जी में इनोवेशन को बढ़ावा दें।

वाणिज्य विभाग ने एक्स पोस्ट में कहा कि यह समझौता जी 20 इनोवेशन मिनिस्टीरियल के दौरान वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद तय हुआ। विभाग ने लिखा, लिखा, लटनिक ने जी20 इनोवेशन मिनिस्टीरियल के दौरान भारत के वाणिज्य राज्यमंत्री जितिन प्रसाद से 6जी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।

उल्लेखनीय है कि भारत के केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने चैपल हिल, नॉर्थ कैरोलिना (अमेरिका) में एक और दो सितंबर को आयोजित जी 20 इनोवेशन मिनिस्टर्स की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक की मेजबानी अमेरिकी वाणिज्य विभाग और व्हाइट हाउस कार्यालय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी (ओएसटीपी) ने की।

ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी में चीन ने भारत का किया समर्थन, सहयोग को बताया अहम

नई दिल्ली, 08 सितम्बर (हि.स.)।

चीन ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह ब्रिक्स सहयोग को बहुत महत्व देता है और इस साल नई दिल्ली में होने वाली नेताओं की समिट की सफल मेजबानी में भारत का समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यह बयान उस सवाल के जवाब में दिया, जिसमें पूछा गया था कि 12–13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली 18वीं ब्रिक्स समिट में चीन की ओर से कौन शामिल होगा और बीजिंग की क्या उम्मीदें हैं। माओ निंग ने कहा, "आपके खास सवाल के बारे में, मेरे पास अभी साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।" साथ ही उन्होंने नई दिल्ली की अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन को दोहराया।

भारत विस्तारित ब्रिक्स समूह के नेताओं की 18वीं समिट की मेजबानी की तैयारी में जुटा है। यह बैठक समूह की स्थापना के दो दशक पूरे होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समिट का मुख्य थीम है– "मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)। दो दिन की इस समिट में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी तथा वरिष्ठ अधिकारी प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इकट्ठा होंगे। चर्चा का फोकस व्यापार, डिजिटल तकनीक, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शासन सुधारों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर रहेगा। मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन, सीमा–पार भुगतान, राष्ट्रीय मुद्राओं का अधिक इस्तेमाल, MSME विकास, डिजिटल व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु रेजिलिएंस, विकास वित्त और न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार जैसे मुद्दे एजेंडे में शामिल हैं।

समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की उम्मीद है। उनका यह दौरा 2019 में ममल्लापुरम में पीएम मोदी के साथ अनौपचारिक मुलाकात के बाद पहला भारत दौरा होगा, जिससे द्विपक्षीय वार्ता भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अन्य प्रमुख नेताओं में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल–सिसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के भी शामिल होने की उम्मीद है।

एशियाई खेल के लिए भारतीय दल को दी गई भव्य विदाई, खेल मंत्री बोले–दबाव को प्रदर्शन में बदलना होगा

नई दिल्ली, 08 सितंबर (हि.स.)।

एशियाई खेल–2026 के लिए भारतीय दल को मंगलवार को नई दिल्ली में भव्य विदाई दी गई। भारतीय ओलंपिक संघ के इस विशेष समारोह में खिलाड़ी, प्रशिक्षक, सहयोगी स्टाफ, अधिकारी और साझेदार शामिल हुए। एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आइची–नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। समारोह में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा सहित भारतीय दल से जुड़े खिलाड़ी, प्रशिक्षक और सहयोगी स्टाफ मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दिन–ब–दिन, साल–दर–साल हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें दबाव को प्रदर्शन में, प्रतिद्वंद्वी को अवसर में और अवसर को उपलब्धि में बदलना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा दल एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा और देश का गौरव बढ़ाएगा।

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, इस अवसर से अभिभूत न हों, बल्कि ऐसा प्रदर्शन करें कि यह अवसर आपको याद रखे। खुद को देखें और याद करें कि आप कितनी दूर तक पहुंचे हैं। आपने एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाई है। अपेक्षाओं का बोझ मत उठाइए, बल्कि उनकी ताकत को अपने साथ लेकर जाइए। मैदान पर उतरिए, प्रतियोगिता का आनंद लीजिए और अपना सब कुछ झोंक दीजिए। आत्मविश्वास, साहस, विनम्रता और इस विश्वास के साथ जाइए कि आप एशिया में किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं।

समारोह का प्रमुख आकर्षण ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले, राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अस्मिता डे, राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता और भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव तथा कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत के साथ आयोजित परिचर्चा रही।

एशियाई खेलों में अपनी भागीदारी को लेकर जूडो खिलाड़ी अस्मिता ने कहा, एशियाई खेल बहुत कठिन होते हैं। जूडो की शुरुआत ही जापान से हुई है और मेरी भारवर्ग में जूडो के कई दिग्गज खिलाड़ी हैं। इनमें दुनिया की सातवीं, आठवीं और 14वीं रैंक की खिलाड़ी भी शामिल हैं। पदक जीतने के लिए मुझे पहले से कहीं बेहतर तैयारी करनी होगी और उनमें से हर एक को हराने के लिए तैयार रहना होगा।

आइची–नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में एशिया के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। भारत ने 2023 एशियाई खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 107 पदक जीते थे। भारतीय ओलंपिक संघ और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को उम्मीद है कि इस बार का दल उस प्रदर्शन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के लिए गौरव लेकर लौटेगा।

अब दांतों का इम्प्लांट होगा आसान, वैज्ञानिकों ने सिंगल पीस डेंटल इम्प्लांट किया विकसित

नई दिल्ली, 08 सितंबर (हि.स.)।

दांतों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इम्प्लांट को और बेहतर बनाने की दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने ऐसा सिंगल पीस डेंटल इम्प्लांट विकसित किया है, जिसमें दो अलग–अलग मजबूत सामग्रियों को एक साथ जोड़ा गया है। इससे मरीज को बार–बार सर्जरी कराने की जरूरत कम हो सकती है। यह तकनीक इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स(एआरसीआई) के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। एआरसीआई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। एआरसीआई के वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट बताया गया कि आमतौर पर दांत का इम्प्लांट तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है। इसमें एक हिस्सा जबड़े की हड्डी में लगाया जाता है, दूसरा हिस्सा उसे दांत के क्राउन से जोड़ता है और तीसरा हिस्सा कृत्रिम दांत यानी क्राउन होता है। इन हिस्सों के बीच हल्की हलचल होने से इम्प्लांट के ढीला होने की समस्या हो सकती है।

इसके अलावा, पारंपरिक इम्प्लांट लगाने के लिए कई मामलों में दो से तीन बार सर्जरी करनी पड़ती है। इससे मरीज को दर्द और असुविधा के साथ उपचार में अधिक समय भी लग सकता है।

इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम मिश्रधातु और यिट्रिया–स्टेबिलाइज्ड जिरकोनिया को मिलाकर एक नई द्वि–परतीय संरचना तैयार की है। दोनों सामग्रियां मजबूत और शरीर के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, नई तकनीक से इम्प्लांट की मजबूती और स्थिरता बढ़ सकती है तथा जबड़े की हड्डी के साथ उसका जुड़ाव बेहतर हो सकता है। साथ ही, इससे पारंपरिक इम्प्लांट की कुछ कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह नई तकनीक भविष्य में दांतों के इम्प्लांट की प्रक्रिया को सरल, कम जटिल और मरीजों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है।

एक साल की वैलिडिटी, लेकिन 90 दिनों की लिमिट; सऊदी अरब ने जारी की उमराह की नई गाइडलाइन्स

नई दिल्ली, 08 सितम्बर।

अगर आप इस साल उमराह यात्रा प्लान करने की सोच रहे हैं, तो आपको नए अपडेट के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल, हाल ही में सऊदी अरब ने उमराह से जुड़े नए नियम जारी किए हैं, जो यह बताते हैं कि आप साल में कितनी बार उमराह के लिए जा सकते हैं और किस तरह आवेदन करना होगा। आइए, आपको सऊदी अरब के इन नए दिशा–निर्देशों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

सऊदी अरब ने उमराह के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा जुलाई महीने से शुरू किया है, जिसकी वैलिडिटी जारी होने के दिन से कुल 365 दिन यानी एक साल तक रहेगी। जब तक यात्रियों का वीजा वैलिड होगा, तब तक वो साल में कई बार यात्रा के लिए जा सकते है।

भले ही साल में कई बार यात्रा करने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन इसकी एक शर्त है, बता दें कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने जो नए नियम जारी किए हैं, उसमें पहले आपको छनेना नामक एप से परमिट लेना होगा।

इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप पैकेज बुक करें तो आपके सर्विस पैकेज और परमिट की तारीख एक दूसरे से मेल खाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वैध वीजा से भी आप बिना परमिट लिए दोबारा उमराह की यात्रा नहीं कर सकते।

इसमें एक जान लेने वाली बात यह भी कि नियमों में साल में कई बार यात्रा करने की छूट तो दी गई है, पर यहां रुकने की कुल अवधि 90 दिन तक ही अधिकतम रखी है। इसे सरल शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि आप साल में 3–4 बार उमराह यात्रा का प्लान करते हैं। ऐसे में आप वहां जा सकते हैं, लेकिन उन 4 बार की यात्रा के कुल दिन 90 दिन तक ही होने चाहिए, यानी पूरे साल वहां ठहरने की अवधि इससे ज्यादा नहीं हो सकती।

अगर आप उमराह की पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आवेदन भी सबसे पहले छनेना एप पर ही करना होगा। एप में जाकर सर्विसेज से जुड़ा पैकेज खरीदना होगा और फिर वीजा के लिए आवेदन करना होगा।

पोखरण रेंज में वायुसेना का 'ड्रोनथॉन' दिखाएगा स्वदेशी ऑपरेशनल क्षमता

नई दिल्ली, 08 सितम्बर (हि.स.)।

घरेलू उद्योग को अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (यूएएस) और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (सीयूएएस) में अपनी काबिलियत और तरक्की दिखाने के लिए भारतीय वायु सेना 14 से 16 सितंबर तक जैसलमेर के पोखरण रेंज में 'आईएएफ ड्रोनथॉन' का आयोजन करने जा रही है। यह इवेंट नई ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ–साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता देखने और आपसी सीख को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस इवेंट में स्थिर और लाइव प्रदर्शन शामिल हैं। इससे आजकल के समाधान पहचानने और उनकी लड़ाई में असरदार होने का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इसमें सर्विलांस और टोही, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, झुंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए ड्रोनथॉन–2026 का मकसद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्ट–अप्स और इनोवेटर्स को जोड़कर स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना है। ऐसी कोशिशों के जरिए वायु सेना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार फोर्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो चुनौतियों का सामना कर सके।

भारतीय वायुसेना को तेजी से बदलते ऑपरेशनल माहौल में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए 'ड्रोनथॉन' इंडस्ट्री, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को एक साथ लाएगा, ताकि वे अनमैन्ड और काउंटर–अनमैन्ड

सिस्टम में अपनी काबिलियत दिखा सकें। तीन दिन के इस इवेंट में वायुसेना सर्विलांस और रिकॉनिसेंस, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेगी। सरकार की यह पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत के मकसद से जुड़ी है, जिसका मकसद घरेलू डिफेंस की क्षमता बढ़ाना है।

दरअसल, सेनाओं में हाल की पहलों ने ड्रोन लॉजिस्टिक्स डिप्लॉयमेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर पर स्टैंडऑफ वेपन इंटीग्रेशन तक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका को बढ़ाया है। ड्रोनथॉन से वायुसेना को ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट की तुलना में तेजी से समाधान पहचानने में मदद मिलेगी। यह इवेंट रक्षा मंत्रालय के स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्रियल बेस बनाने की प्रतिबद्धता का भी संकेत देता है, जिससे गोला–बारूद प्रोडक्शन, मिसाइल सिस्टम और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म पर सेनाओं और घरेलू डिफेंस फर्मों के बीच चल रही पार्टनरशिप और मजबूत हुई है।